[Mr. Chairman]

defying Section 144, etc. But, we have asked for a detailed report. The Home Minister, anyhow, is very much there in the House. He is going to respond to it. *...(Interruptions)...* आप बैठ जाइए, प्लीज़।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, let the Home Minister make a statement. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Then, again, the same thing will happen and you will be at a loss. *...(Interruptions)...*

DR. SANTANU SEN: Sir*...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I will not allow this. Please sit down. *...(Interruptions)...* I do not know in what way you are reading the procedures and then raising it. I have obliged you. I have said that I am taking it on record. I have given opportunity to your leader also. And, if it becomes a habit, then it will be very difficult. Now, the hon. Home Minister to respond. Then, Members from Assam will be given priority, and other Members also, if they have any clarifications, will be allowed. *...(Interruptions)...* That is the Zero Hour now. *...(Interruptions)...* It has been given priority. Now, Shri Rajnath Singh.

DISCUSSION ON THE FINAL DRAFT OF THE NATIONAL REGISTER OF CITIZENS IN ASSAM* ... *Contd.*

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, शांति से सुनिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, गंभीर और नाज़ुक मामला है।

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एनआरसी ड्राफ्ट को लेकर बहुत ही गंभीर चर्चा इस सदन में हुई है। मैं लगभग 21-22 वर्षों से संसद के इस सदन में अथवा उस सदन में अपनी भूमिका का निर्वहन एक संसद सदस्य के रूप में कर रहा हूं। मैंने देखा है कि जब कभी भी संसद के सामने नेशनल प्राइड, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी, इंटिग्रिटी और सोव्रेनिटी का सवाल खड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा सदन पूरी तरह से एकमत रहा है, पूरी तरह से उसमें कंसेसस रहा है। जहां तक NRC draft का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि इसको लेकर कहीं पर कोई apprehensions रहे होंगे, कहीं पर कोई confusion रहा होगा। इस कारण से चर्चा कभी नर्म हुई तो कभी गर्म हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरा clarification हो जाने के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी।

---

* Further discussion continued from 01.08.2018.

सबसे पहले तो मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि यह ड्राफ्ट जो 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुआ है, वह final draft नहीं है, वह final NRC नहीं है, बल्कि यह NRC draft है। सभापति महोदय, इस NRC के background पर भी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। NRC को update करने की प्रक्रिया 15 अगस्त, 1985 को साइन किए गए Assam Accord के अनुसार प्रारम्भ हुई। असम में 1951 में भी census के आधार पर NRC तैयार किया गया था। 1979 से 1985 के बीच illegal foreigners के विरुद्ध चलाए गए असम आंदोलन के बाद केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, All Assam Students' Union और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच असम समझौता हुआ था। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय हमारे देश के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। उस समझौते में असम में illegal foreigners की पहचान करने के लिए 24 मार्च, 1971 की एक cutoff date निर्धारित की गयी थी। इस समझौते को implement करने हेतु NRC को update करने का निर्णय तत्कालीन प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2005 में राज्य सरकार और All Assam Students' Union के साथ हुई एक बैठक में लिया गया था।

सभापति महोदय, 6 दिसम्बर, 2013 को NRC updation के लिए भारत सरकार द्वारा notification जारी किया गया था। यह सारा कार्य बेहद meticulous तथा transparent तरीके से किया गया है। पूरे राज्य में 2,500 NRC सेवा केन्द्र इस कार्य के लिए स्थापित किए गए हैं। एक partial draft दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित किया गया तथा final draft दिनांक 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया। जो भी आवश्यक जानकारी की आवश्यकता थी, वह सारी जानकारी हासिल करने के बाद और उसका verification करने के पश्चात ही यह NRC drafts तैयार किया गया, जो 30 दिसम्बर को publish किया गया है। उसमें उन व्यक्तियों अथवा उनके वंशजों के नाम शामिल हैं, जिनके नाम दिनांक 24 मार्च, 1971 तक के electoral roll अथवा NRC 1951 में दर्ज हुए थे। Legacy establish करने के लिए 12 दूसरे documents, जैसे land records, passport, जीवन बीमा पॉलिसी, Employer's Certificate आदि भी allow कर दिए गए थे। यदि एक document नहीं है तो इनमें से कोई भी document आप दे सकते हैं। अन्य राज्यों से आकर असम में रहने वाले भारतीय नागरिक भी 1971 से पहले के भारत में कहीं का भी certificate of residence दिखाने पर योग्य माने जाएंगे, यानी उनका नाम NRC में शामिल कर लिया जाएगा।

मैं पुनः इसे clarify कर देना चाहता हूं कि यह केवल ड्राफ्ट है, न कि final NRC. NRC तैयार करने का जो पूरा process चला है, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के supervision में ही चला है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया की नियमित रूप से monitoring कर रहा है। 31 जुलाई, 2018 को भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट ने कुछ और निर्देश भी दिए हैं। भारत सरकार तथा असम राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि time-bound manner में सभी genuine Indian citizens के नाम NRC में शामिल कर लिए जाएं। यह सारी प्रक्रिया पूरी तरह से fair है और साथ ही साथ objective है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न ही आगे कोई भेदभाव होगा। इस प्रकार के आरोप यदि कोई लगाता है तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा। मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहता हूं कि final NRC के पहले सभी को legal provisions के अनुसार claims and objections फाइल करने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा

[श्री राजनाथ सिंह]

फाइनल एन.आर.सी. के पश्चात भी सभी संबंधित व्यक्तियों को Foreigners Tribunal के पास जाने का पूरा अवसर मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि जिन व्यक्तियों का नाम फाइनल एन.आर.सी. में शामिल नहीं हो पाएगा, तो वे Foreigners Tribunal को एप्रोच कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसी के विरुद्ध कोई भी coercive action नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही मानता हूं कि कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनके द्वारा अनावश्यक रूप से एक डर का माहौल पैदा किया गया है। इस मामले में कुछ लोगों के द्वारा गलतफहमियां फैलाने की कोशिश भी की गई हैं। कुछ vested interests वाले व्यक्तियों के द्वारा social media पर propaganda चलाया जा रहा है, ताकि इस मामले को internationalise किया जा सके तथा communal harmony को प्रभावित किया जा सके, यानी यह communal disharmony पैदा करने की एक कोशिश है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, वह कम से कम इतना तो जानना चाहेगा कि हमारे देश में कितने हमारे nationals हैं और कितने foreigners हैं। इसकी जानकारी रखना किसी भी देश के लिए बहुत स्वाभावित है। यह उसका दायित्व बनता है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह विषय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और मैं इस संबंध में सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। दिनांक 29 जुलाई, 2018 को असम के मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गुवाहाटी में एक all-party meeting हुई थी और उस मीटिंग में एन.आर.सी. बनाने के लिए सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन भी दिया था और इसमें सभी प्रमुख दल शामिल थे। सभापति महोदय, मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि peace, harmony और public order को maintain किया जाएगा। हमारी सरकार ने इस कार्य में असम में राज्य सरकार को assist करने के लिए, उन्होंने जितनी भी force की मांग की थी, उन्हें वह force मुहैया कराई जा चुकी है। चर्चा के दौरान कुछ और भी प्रश्न उठाए गए हैं, जिन सम्मानित सदस्यों ने प्रश्न उठाए थे, उनमें से कुछ सम्मानित सदस्य यहां पर मौजूद नहीं हैं। फिर भी, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। चूंकि चर्चा की शुरुआत हमारे लीडर ऑफ द अपोज़िशन, गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से हुई थी इसलिए पहले उन्हें के द्वारा जो apprehensions यहां पर express किए गए थे, उनका उत्तर मैं देना चाहूंगा। आज़ाद साहब ने यह कहा था कि 40 लाख व्यक्ति शामिल नहीं हुए हैं, उनके परिवारों को मिलाकर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं यह क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये 40 लाख परिवार नहीं हैं, बल्कि ये 40 लाख व्यक्ति हैं, इसलिए इसको लेकर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 3,29,91,384 व्यक्तियों ने एन.आर.सी. के लिए एप्लाई किया था और उसमें से 2,89,83,677 व्यक्ति एन.आर.सी. के ड्राफ्ट में शामिल हो गए हैं। मैं सुखेन्दु राय जी, जो कि इस समय मौजूद नहीं हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री देरेक ओब्राईन (पश्चिमी बंगाल): सर, वे मौजूद नहीं हैं because उनको तो arrest कर जेल में बंद कर दिया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, Mr. Derek. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... Let him complete. ...*(Interruptions)*... No argument is allowed.

...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... You are a senior parliamentarian. ...*(Interruptions)*... You know that. ...*(Interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, सुखेन्दु राय जी ने एक प्रश्न किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 5 दिसम्बर, 2017 को जो आदेश हुआ था, उस आदेश की भी चर्चा की थी। इसमें पृष्ठ 7 पर यह कहा गया है कि असम के original inhabitants व भारत के अन्य प्रदेशों से आए नागरिक बराबरी के माने जाएंगे और उनको नागरिकता प्राप्त करने का भी समान अवसर मिलेगा। वास्तव में ऐसा ही किया जा रहा है। जैसी सुप्रीम कोर्ट ने हमसे अपेक्षा की है, वैसा ही किया जा रहा है। सभी भारतीय नागरिक जो अन्य राज्यों से असम में आए हैं और वर्ष 1971 से पहले, भारत का कहीं का भी certificate of residence दिखाने पर, एन.आर.सी में उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा और अब तक शामिल किए गए हैं। प्रो. राम गोपाल यादव जी और श्रीमती विजिला सत्यानंत ने भी इंडियन सिटिज़न्स और उनके बच्चों का प्रश्न यहां पर उठाया था, जो 24 मार्च, 1971 के उपरान्त असम में आए हैं। सभापति महोदय, मैं इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी आवश्यक प्रमाण पत्र NRC में शामिल किए दिए जाने के लिए अपेक्षित हैं, वे सारे आवश्यक प्रमाण पत्र देने पर किसी भी भारतीय का नाम नहीं छूटेगा और हर भारतीय नागरिक का नाम NRC में शामिल किया जाएगा। Claims and objections की प्रक्रिया में इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

प्रो. मनोज कुमार झा जी ने एक प्रश्न किया था और उस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जिसने NRC के लिए एप्लाई किया है, उसको अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। इसके लिए कई वैकल्पिक डाक्युमेंट्स दिए जा सकते हैं, जिनकी चर्चा मैंने पहले भी की है, जैसा कि पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी है, सर्विस डाक्युमेंट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एम्पलॉयमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब दिए जा सकते हैं, जो कि 24 मार्च, 1971 के पहले issue किए गए हैं।

सभापति महोदय, इस प्रकार से जो NRC का प्रोसेस चला है, नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ही इसे तैयार किया गया है। सभापति महोदय, मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र देने एवं NRC में शामिल होने का पूरा अवसर मिलेगा। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं। 30 जुलाई को जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, वह ड्राफ्ट है और claims and objections हर व्यक्ति, जो भारत के किसी भी कोने से असम में आया है, उसको पुनः अवसर मिलेगा, जिसमें वह अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सके, अपनी नागरिकता को प्रूव कर सके। NRC updation exercise भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत, भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा साइन किए गए Assam Accord के अंतर्गत पूर्णतया ट्रांसपेरेंट तरीके से की जा रही है। NRC का विषय हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हम सभी को इस मुद्दे पर पूरी संवेदनशीलता के साथ उत्तरदायी भी होना चाहिए। सभापति महोदय, हम इस एक्सरसाइज़ को इसके logical conclusion तक ले जाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं, लेकिन हम यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि न तो किसी के साथ कोई भेदभाव होगा और न ही किसी को अनावश्यक harassment का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं पुनः सदन को अपनी तरफ से आश्वस्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोसेस चलाया जा रहा है, वह फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। यदि कहीं पर भी किसी को किसी प्रकार की शिकायत होगी, तो उस शिकायत का भी निस्तारण किया जाएगा।

श्री सभापतिः धन्यवाद मंत्री जी। डा. मनमोहन सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?

डा. मनमोहन सिंह (असम)ः नहीं।

MR. CHAIRMAN: The name of the former Prime Minister was also taken. That is why I asked him. Now, Shri Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, first of all, I extend my thanks to the hon. Home Minister for giving this reply. He has given the historical background of NRC in which it has been established that a wrong message had gone to the country that the Congress is against NRC. But, now, from the statement of the hon. Home Minister, it has clearly been justified that it is the Congress Party which initiated NRC. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary? ...*(Interruptions)*... Please look at the time because I have to give opportunity to all.

SHRI RIPUN BORA: Sir, I want to add one more thing. With the statement of the hon. Home Minister, it is clear that Shri Rajiv Gandhi, the former Prime Minister, understood the danger of the people of Assam in the field of cultural, social, economic and political security and for that purpose, the Assam Accord was done by our beloved Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. It was done in order to protect the people of Assam.

Now, Sir, I have to make only a few suggestions to the hon. Home Minister. There is urgent requirement for modification of some guidelines. So far as 40 lakh people are concerned, here we have seen, most of them are women and children below 18 years. Sir, all of them are Indian citizens. Names of women have been dropped only because there is a provision in the guideline of NRC that a married woman would have to submit her linkage certificate from her parents' native place. That linkage certificate is to be given by the Gram Panchayat Secretary. But, what has happened in many cases is that the Gram Panchayat Secretary has given the certificate but the verification officer has instructed for another supporting document. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Right, thank you, Ripunji. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, this is a very ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, this is one. ...*(Interruptions)*... The second thing is about the children. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have another Member from your Party. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, one minute. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापतिः आप लोग बीच में इस प्रकार से interfere मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**... मुझे मालूम है कि एक Member कांग्रेस की ओर से बोलने के लिए और हैं। ...**(व्यवधान)**... I have to complete it by 12 o' clock. ...*(Interruptions)*... He would be losing the opportunity. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, my last point is this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Others should not stand. Please sit down. ...*(Interruptions)*... I am allowing him. ...*(Interruptions)*... What are you doing? ...*(Interruptions)*... This should have happened three days back. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, then, in these 40 lakhs, there are several lakhs of children who are below 18 years and because of being below 18 years, there is requirement of birth certificate or school certificate. But, in Assam - the remote areas, the inaccessible areas - due to illiteracy, their parents have no birth certificate and no school certificate, and the venture school certificate, which was given, was rejected. Because of that also, names of many Indian citizens may have been dropped.

MR. CHAIRMAN: Right, thank you.

SHRI RIPUN BORA: My last submission to the hon. Home Minister, and one point of information for my TMC friends also, is that in case of migration of the married women, the Assam NRC Authority has issued letters to different States for proof of their linkage certificate. In the Supreme Court on 27.03.2018, the Registrar General of India gave the information that only 30.63 per cent reply has come. As far as West Bengal is concerned, 1,20,000 applications were forwarded by the NRC Authority to the West Bengal Governor but only 15,000 replies have come so far. ...*(Interruptions)*... So, because of that also, some genuine names have been dropped.

So, now, my suggestion to the hon. Minister is to modify. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Ripunji, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: These are all technical grounds and because of these technical grounds the names of Indian citizens have been left out. So, my humble submission is to

[Shri Ripun Bora]

modify and simplify the guidelines and to extend the deadline for submission of claim forms, which has been given as 27th of September, it is a very short time and it should be extended.

My second suggestion is this. The Supreme Court has already given order that they should not take any apparent view of treating these 40 lakh people as foreigners. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Right, thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Though in Assam, an all-party meeting was convened by the Assam Government, I would like to suggest that at the national level also, there should be an all-party meeting so that all political parties can be taken into confidence. ...*(Interruptions)*... Thank you Mr. Chairman, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... Very constructive suggestions. ...*(Interruptions)*... Shri Bhubaneswar Kalita, be very brief, please. ...*(Interruptions)*... I have to cover all before the Question Hour. Please understand. See, how many hands are being raised? You are from the State and you are also a senior Member. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, how many minutes are you going to give me?

MR. CHAIRMAN: Normally, the clarifications are for one or two minutes.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: If two minutes, then, there should not be any interruptions.

MR. CHAIRMAN: Okay, no problem. Nobody should interrupt him.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, as the hon. Home Minister has already given the details and background of the NRC, I will not go into that. While I am one with the Leader of the Opposition in welcoming this NRC because NRC was first brought into effect in the year 1951, that is, after partition, after Independence of India, – that is the basis of the present NRC — so many things have happened in between which necessitated the updating of this NRC. There was a report. One of our hon. Members has already raised it that there was a report from one Governor that four lakh foreigners, Bangladeshis, are in Assam. That was again followed by a Chief Minister saying that it would be more than that. Another Chief Minister said that it would be nearly seven lakhs.

So, it was necessitated that an updating be done. And, this demand was there and I want to tell you the background that until 1984, there were agitations, and in 1985, the Accord was signed. In the Accord, this was one of the points that NRC would be updated. Sir, from 1985, there were two Opposition Governments, non-Congress Governments, and nothing was done. In 2001, the then Congress Government took up this with a tripartite meeting for updating of the NRC. Sir, the Supreme Court order is subsequent, and before that, the work was started. And, with the order of the Supreme Court, the updating has been completed now. I compliment them for it.

MR. CHAIRMAN: What is your suggestion or question now?

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Yes, I am coming to the question now. Sir, my first question is or the first clarification that I want to ask is that most of the people, those whose names do not appear in the NRC belong to the poorer sections of the society. Those who are rich; those who are literate, they will find their way to get into the NRC but what about the poorer sections who could not even come to register their names in the NRC? I would like to know whether the Government will provide legal aid to those poorer sections of people so that they get justice.

MR. CHAIRMAN: Right, thank you.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: My second question is, Sir, hon. Home Minister had bilateral meeting with his Bangladesh counterpart.

MR. CHAIRMAN: You had three minutes. ...*(Interruptions)*... You had three minutes, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: And, the Bangladesh and the Indian Home Minister have signed a joint communique and in that it has been mentioned that the Indo-Bangladesh border is safe and secure. The other day, in reply to a question, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs has also said that. Sir, my question is or my clarification is, whether this issue was discussed with the Bangladesh Government.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Because with such number of people who are out of NRC and doubted they are Bangladeshi, I would like to know whether the Home Minister has taken up this matter with his Bangladesh counterpart...

MR. CHAIRMAN: Thank you, Kalitaji. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: And, whether some bilateral discussion will be done by the Home Minister. Thank you very much, Mr. Chairman, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Prof. Manoj Kumar Jha. It will be odd for me to advise the senior Members. They should restraint themselves and take the example of LoP who always confines to time.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I will follow.

MR. CHAIRMAN: Very good. Please.

प्रो. मनोज कुमार झा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर इतिहास की समग्रता की जरूरत थी, न कि एक एकांगी दृष्टिकोण की और आपने उस समग्रता का परिचय दिया। कई सारे जो साक्ष्य हैं, वे सदन के माध्यम से अवाम के बीच जाएंगे। सर, अगर 40 लाख व्यक्तियों में से 10 लोग भी document के बाद सही पाए गए, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बीते 10-12 दिनों से ये 'घुसपैठिए' के टाइटल में जी रहे हैं। प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोग इन्हें 'घुसपैठिए' बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपकी और NRC Co-rdinator की ज़ुबान में थोड़ी healing हुई है। मैं समझता हूं कि इस healing touch को और बढ़ाना होगा।

MR. CHAIRMAN: Right.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं एक आखिरी टिप्पणी करूंगा।

MR. CHAIRMAN: He has to respond before 12'o clock.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा।

MR. CHAIRMAN: You are capable. Please finish it.

प्रो. मनोज कुमार झा: अगर possible हो, तो वैसे लोगों के लिए थोड़ी legal aid, hand-holding होनी चाहिए, जिनके परिवार के तीन सदस्य नागरिक हैं, लेकिन दो सदस्य नागरिक नहीं हैं। नागरिकता के ऊपर मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर हम इसको समुदाय और परिवार के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तो यह पूरा का पूरा मामला संवेदनहीन लगेगा।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Manojji. These all are asking clarifications only. Now, Shri Majeed Memon.

श्री माजीद मेमन (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, हम आदरणीय गृह मंत्री जी के स्पष्टीकरण का स्वागत करते हैं। उन्होंने जो बात कही, उसे दोहराते हुए मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि यह final नहीं है, हर व्यक्ति को दोबारा मौका दिया जाएगा और अगर उसके पास अधिकार है, तो उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हम इसका दिल से स्वागत करते हैं। महोदय, बंगलादेश की सरकार की तरफ से यह जवाब आ चुका है कि हम इन लोगों को accept नहीं करेंगे। दोबारा scrutiny

करने के बाद हो सकता है कि 40 लाख का यह नम्बर घट कर 30 लाख पर रुक जाए या 25 लाख पर रुक जाए। उनके बारे में भारत सरकार का क्या विचार है, क्या प्लान है और उनका क्या किया जाएगा, आप कृपया इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Memonji. Now, Shri Javed Ali Khan. Please give suggestion or ask question.

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): I will ask one clarification and not give any suggestion. माननीय सभापति जी, NRC से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह एक समझौते के तहत बना है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उसके निर्देशों के तहत ही इसका काम हो रहा है। जब से 40 लाख लोगों के NRC में जगह न पाने का मामला सामने आया है, तब से कुछ ऐसे विशेष नाम भी सामने आए हैं, जिनके नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं हैं। असम के दो विधायकों के नाम उसके अंदर शामिल नहीं हैं, वहां की Assembly के एक ex-Deputy Speaker रहे हैं, जिनके नाम उसके अंदर नहीं हैं। हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद साहब, उनके परिवार के लोगों के नाम भी उसमें छूट गए हैं।

महोदय, इसके साथ यह भी हो रहा है कि हमने उन सब 40 लाख लोगों को 'घुसपैठिए' की संज्ञा देना शुरू कर दिया है। चार दिन से टीवी पर बहस चल रही है, जिनमें उनके लिए लगातार 'घुसपैठिए', 'घुसपैठिए', 'घुसपैठिए' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि अभी तक फाइनल ड्राफ्ट भी नहीं आया है। एक बड़ी पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ...(व्यवधान)...

†**جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش):** مانّنیے سبھا پتی جی، این-آر-سی- سے ہمارا کوئی ورودھ نہیں ہے، کیوں کہ وہ ایک سمجھوتے کے تحت بنا ہے اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں، اس کے نردیشوں کے تحت ہی اس کا کام ہو رہا ہے۔ جب سے چالیس لاکھ لوگوں کے این-آر-سی- میں جگہ نہ پانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، تب سے کچھ ایسے خاص نام بھی سامنے آئے ہیں، جن کے نام اس لسٹ کے اندر نہیں ہے۔ آسام کے دو ودھایکوں کے نام اس کے اندر شامل نہیں ہے، وہاں کی اسمبلی کے ایک سابق ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، جن کے نام اس کے اندر نہیں ہیں۔ ہمارے دیش کے جو سابق راشٹرپتی رہے ہیں، شری فخرالدین علی احمد صاحب، ان کے پریوار کے لوگوں کے نام بھی اس میں چھوٹ گئے ہیں۔

مہودے، اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے ان سب چالیس لاکھ لوگوں کو 'گھس-پیٹھئے' کی سنگیا دینا شروع کر دیا ہے۔ چار دن سے ٹی-وی- پر بحث چل رہی ہے، جس میں ان کے لئے لگاتار 'گھس-پیٹھئے'، 'گھس-پیٹھئے'، 'گھس-پیٹھئے' شبد کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ابھی تک فائنل ڈرافٹ بھی نہیں آیا ہے۔ ایک بڑی پارٹی کے نیتا نے پریس کانفرنس کرکے ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu script.

MR. CHAIRMAN: I agree with you, but the point is, the media should be careful. That is all. ...*(Interruptions)*... Next is Shrimati Vijila Sathyananth. ...*(Interruptions)*...

श्री जावेद अली खान: एक बड़ी पार्टी के नेता ने प्रेस कांफ्रेंस करके उन 40 लाख लोगों के बारे में यह कहा कि वे घुसपैठिए हैं। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان** : ایک بڑی پارٹی کے نیتا نے پریس کانفرنس کرکے ان چالیس لاکھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ 'گھس-پیٹھئے' ہیں ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Javed Aliji, please. I understand. ...*(Interruptions)*...

श्री जावेद अली खान: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से उन 40 लाख लोगों को, जिनके नाम किसी भी वजह से NRC में आने से छूट गए हैं ...(**व्यवधान**)...

† **جناب جاوید علی خان** : میں مائنے منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس طریقے سے ان چالیس لاکھ لوگوں کو، جن کے نام کسی بھی وجہ سے این-آر-سی۔ میں آنے سے چھوٹ گئے ہیں ...(مداخلت)...

श्री सभापति: मैं समझ गया हूं। Please don't repeat. Otherwise, you will not get the reply then.

श्री जावेद अली खान: क्या आप उन्हें 'घुसपैठिए' की संज्ञा दिए जाने से रोकेंगे?

†**جناب جاوید علی خان** : کیا آپ انہیں 'گھس-پیٹھئے' کی سنگیا دئے جانے سے روکیں گے؟

MR. CHAIRMAN: You have made a very good point. But you could have confined to that.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I again want to reiterate that from different parts of our nation, people have gone and settled in Assam. They are possessing Aadhaar cards, ration cards, school certificates. They are also possessing the marriage certificates. There are people from South who are married to Assamese people. They possess all that but their name is not in the NRC.

MR. CHAIRMAN: So what is your suggestion?

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: I want to know whether the modalities will be changed or revised so that these people, who have migrated from different parts of the country, especially, from the South, can be proved that they are Indians, that they are the citizens of this country.

†Transliteration in Urdu script.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I have only two questions. Number one is, will the time-limit be extended? The Government will have to clarify that. Number two, the Government will not allow any action. I think no action should be taken against those who do not find place in the draft NRC.

MR. CHAIRMAN: Right. These are very basic points, which you raised that day also.

SHRI D. RAJA: Yes, Sir. These are my two questions and the Minister should clarify.

MR. CHAIRMAN: Shri T.K. Rangarajan.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, first, I thank the Home Minister for his reply. My point is, when you enumerate that no caste or no religion should be taken into account, nobody should be punished, I request the Home Minister that in the all-party meeting in the State and at all India level also, before you conclude this, give them more opportunity and extend the time.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Derek O'Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have two suggestions and two questions. Sir, my first suggestion is this. We have been going on with this for 47 minutes now. We have heard the name of only one State, Assam. This is not just an Assam issue. This is an issue for Rajasthan. This is an issue for Punjab. This is an issue for UP. This is an issue for Bengal. This is a national issue, a human rights issue, a humanitarian issue.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRI DEREK O'BRIEN: So, let us not get stuck in with Assam.

MR. CHAIRMAN: Please don't go into the explanation. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my second point is, this is classical double-speak. What is the real voice of this Government? Is the real voice of this Government what the Home Minister says here or what the BJP Party President says outside? ...*(Interruptions)*... We need to know. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. Please don't get into politics. ...*(Interruptions)*... Don't get into politics at all. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: We need to know this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You ask the clarifications, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: My clarification is...*(Interruptions)*... Why? ...*(Interruptions)*... When I say, 'BJP Party President'...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: This is not about a party. Here, we are not discussing about parties. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we are hearing two voices. ...*(Interruptions)*... Let the Home Minister...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Derek, do you want to ask the supplementary? ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Yes, Sir. I have not asked the question. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Then, please do. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... No mention of any parties, please. ...*(Interruptions)*... कृपया बैठे-बैठे मत बोलिए। Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, when the Home Minister spoke for 20 minutes, we listened to him. Get them seated first, Sir...*(Interruptions)*... Sir, the Home Minister spoke for 20 minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: For this much you are getting this impatient! I have been patient for how many days! ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, no, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nobody should speak. ...*(Interruptions)*... Bhupender*ji*, sit down. ...*(Interruptions)*... Without the Chairman's permission, nobody should speak or even make comments. Nothing will go on record. Don't test my vocal cords. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: I am quoting the Home Minister, what he just said in the House.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRI DEREK O'BRIEN: "Communal disharmony is being spread." Yes, Sir. It is being spread. But, who is spreading it? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... This is all political ...*(Interruptions)*... This is a political allegation. ...*(Interruptions)*... I will have to go to the next name. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: I am quoting it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is the clarification? ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir. You have to protect me... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If you are making allegations, how can I protect you? If you confine yourself to the subject, I can protect you. I can go out of the way also to protect you.

SHRI DEREK O'BRIEN: Everything is peaceful, two of my colleagues from Rajya Sabha, phoned up my colleague MPs. They went yesterday, and they said, " Section 144 was on." They said, " They don't want to meet big groups. They will go in groups of two, Sir." ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek, please. What is your point? You are making comments, and then, counter comments. Ask clarification. What is your clarification?

SHRI DEREK O'BRIEN: I have asked two clarifications. Let me ask my clarification.

MR. CHAIRMAN: You can't take the time and deprive opportunity to others. At twelve o' clock, he has to reply. If you don't want reply, then, ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have been a Quiz Master. You know how to calculate the time also ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, let me clarify. I am no Quiz Master. I am the Parliamentary Party Leader in Rajya Sabha from the TMC. Please correct this, Sir. I am no Quiz Master.

MR. CHAIRMAN: Okay; you don't know quiz. I leave it. Okay.

SHRI DEREK O'BRIEN: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: What is your clarification?

SHRI DEREK O'BRIEN: The Home Minister must clarify whether he approves of all those statements coming out, including, of shooting people, etc. We must not double-speak.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my last question is, as I said, we cannot allow refugees in our own country. We have to accept this.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, if everything is so calm, then, what happened yesterday to my colleagues? We have raised the privilege question. ...*(Interruptions)*... Sir, let me ask my last question. If there are sixteen documents needed to prove the citizenship or not the citizenship, then how, the higher Constitutional authorities, could not produce one document for their graduation certificate?

MR. CHAIRMAN: See, on such an issue, larger issue, concerning the nation's security and sovereignty, one has to be very serious.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): I just want two clarifications. The first one is, among the people, who are excluded from the NRC, are undoubtedly, large numbers of people who are not citizens of India. We don't know the numbers. So, they can be classified into two categories. Some of them are, what might be called economic migrants. But, there are people who are refugees, who have fled from persecution in neighbouring countries. What is the attitude of the Government of India towards people who are refugees? That is number one. Number two, can we ask the Home Minister for some assurance that no person, who is not a citizen of India, should be included in one of the most democratic functions, which is the voting right because just as Indians cannot be excluded from voting, we cannot have people, who are not citizens of India, voting?

MR. CHAIRMAN: Right. Thank you. Now, Shri Anand Sharma.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I thank the Home Minister.

आपने आश्वस्त किया है कि किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वह अपना क्लेम फाइल न करे और final list न जारी हो जाए।

सर, मुझे आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से एक बात पूछनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस NRC की draft list आने के बाद सरकार को और देश को एक बात कही है कि इस पर जो modalities हैं, जो standard operating procedure हैं, उनको streamline किया जाए और notify किया जाए। वह कब तक होगा, यह गृह मंत्री जी आश्वस्त करें। साथ ही, पहले भी जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, उनको आप कैसे जानकारी पहुंचाएंगे? क्या आप अनपढ़ लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए विशेष कैम्प्स लगाएंगे? स्पष्ट प्रश्न है कि इसका सीधा प्रभाव अन्य राज्यों पर ही नहीं पड़ता है, परन्तु भारत

के पड़ोसी देशों के साथ – अभी प्रश्न आया था कि आप हमारे पड़ोसी मित्र देश के पास गये, वहां आपकी बातचीत हुई, बंगलादेश के साथ। इस सरकार ने...

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री आनन्द शर्मा: सर, एक मिनट। यह गम्भीर बात है।

श्री सभापति: टाइम नहीं है। 12 बजने वाले हैं। I have to go to Question Hour.

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैं सवाल तो पूछ लूं? ...**(व्यवधान)**... मैं एकदम से दो सवाल पूछ लेता हूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री आनन्द शर्मा: मेरा पहला प्रश्न है कि सरकार ने भारत की संसद को बताया है कि केवल 2.4 लाख लोग असम के doubtful voters हैं, सरकार के गृह राज्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजु ने यह सदन को बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही स्थिति है, क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बहुत ज्यादा लोग ...**(व्यवधान)**... इनमें बाहर के हैं।

दूसरी बात, मैं यहां इतिहास में नहीं जाता, NRC 1951 से और 1985 के Accord से असम - specific है। Sir, this is important. NRC updating is Assam-specific. The Home Minister must clarify what is the position because, today, when there is a talk that NRC exercise will be extended to other States, it has created huge panic and fear in the country. That should be clarified.

MR. CHAIRMAN: Now, the Leader of the Opposition.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I have a question.

MR. CHAIRMAN: No, I can't allow. The Leader of the Opposition is the last one and then we will go to Question Hour.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhattacharya, please sit down. ...*(Interruptions)*... I can't because it can't be an extension of the discussion. The Leader of the Opposition is on his legs, please sit down. ...*(Interruptions)*... That means, you are not interested in hearing replies! What can I do?

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। असम से मेरा association तकरीबन 41 वर्षों से है, जब मैं Youth Congress में था। आज से 31 या 32 साल पहले, जब मैं 1986 में, Accord के तुरंत बाद, Minister of State for Home Affairs था, उस समय दो Minister of State for Home Affairs थे और वर्क allocation में मेरे पास Mizoram Accord, Assam Accord and Punjab Accord था। इस संबंध में यहीं दिल्ली में मेरी दर्जनों meetings उस समय के मंत्री, श्री प्रफुल्ल मोहंता और दूसरे मंत्री, श्री थुंगन के साथ हुई थीं। तब से लेकर, 1986 से लेकर आज तक इस बारे में जब कभी भी चर्चा होती है तो मैं इसके साथ associated रहता हूं।

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

यहां दो-तीन चीज़ें माननीय गृह मंत्री जी ने बताईं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत की सुरक्षा, स्वतंत्रता और territorial integrity बहुत अनिवार्य है। इसमें कोई compromise नहीं हो सकता - चाहे विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो। यह भी अनिवार्य है कि देश के पास ऐसी सूची होनी चाहिए कि उसके citizens कौन हैं। इतना विशाल देश है। कश्मीर से लेकर North-East और दक्षिण तक चारों तरफ हमारे borders हैं और हम अपने borders दुनिया के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। यहां सुरक्षा का मुद्दा भी है और संख्या का मुद्दा भी है लेकिन इसके साथ-साथ मैं, कल television देख रहा था, जिसमें दिखाया गया कि एक आदमी जो आर्मी में 30 साल service करने के बाद रिटायर हुआ और दूसरा Air Force से 30 साल की service करने के बाद रिटायर हुआ है, उन दोनों के नाम लिस्ट में नहीं हैं। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने बाप का 1951 वाला certificate दिया और दूसरे ने 1947 वाला अपनी मां का certificate दिया। अब इन Army and Air Force के दो लोगों ने, एक ने 1947 वाला अपनी मां का certificate दिया और दूसरे ने 1951 वाला अपने बाप का certificate दिया हो ...(**व्यवधान**)...

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** مہودے، میں زیادہ وقت نہیں لونگا۔ آسام سے میرا ایسوسی ایشن تقریباً 41 سالوں سے ہے، جب میں یوتھ کانگریس میں تھا۔ آج سے 31 یا 32 سال پہلے، جب میں 1986 میں، Accord کے فوراً بعد، Minister of State for Home Affairs تھا، اس وقت دو Minister of State for Home Affairs تھے اور ورک ایلوکیشن میں میرے پاس Mizoram Accord, Assam Accord and Punjab Accord تھا۔ اس سلسلے میں یہیں دہلی میں میری درجنوں میٹنگس اس وقت کے منتری، شری پرفل موہنتا اور دوسرے منتری، شری ٹھنگن کے ساتھ ہوئیں تھیں۔ تھب سے لیکر، 1986 سے لیکر آج تک اس بارے میں جب کبھی بھی چرچہ ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ ایسوسی ایٹیڈ رہتا ہوں۔

یہاں دو تین چیزیں مانیئے گرہ منتری جی نے بتائیں۔ میں مانیئے گرہ منتری جی کا سواگت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی سُورکشا، سوتنترتا اور territorial integrity بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائیز نہیں ہوسکتا۔ چاہے وپکش ہو یا ستّہ دھاری پارٹی ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دیش کے پاس ایسی سُوچی ہونی چاہیئے کہ اس کے سٹیزن کون ہیں۔ اتنا وِشال دیش ہے۔ کشمیر سے لیکر نارتھ ایسٹ اور دکشن تک چاروں طرف ہمارے بارڈرس ہیں اور ہم اپنے بارڈرس

†Transliteration in Urdu script.

دنیا کے لیے کھلے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں سورکشا کا مدعا بھی ہے اور تعداد کا مدعہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ، میں کل ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، جس میں دکھایا گیا کہ ایک آدمی جو آرمی میں تیس سال سروس کرنے کے بعد ریٹائیر ہوا اور دوسرا ائیرفورس سے تیس سال کی سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہوا ہے، ان دونوں کے نام لِسٹ میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا 1951 والا سرٹیفکیٹ دیا اور 1947 والا اپنی ماں کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اب ان آرمی اینڈ ائیرفورس کے دو لوگوں نے، ایک نے 1951 والا اپنی ماں کا سرٹیفکیٹ دیا اور دوسرے نے 1947 دوسرے نے والا اپنے باپ کا سرٹیفکیٹ دیا ہو۔ ---(مداخلت)---

श्री सभापतिः एक ही मिनट बचा है, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... You have to be brief, please.

श्री गुलाम नबी आज़ादः यह television पर discussion चल रहा था। इस तरह से माननीय गृह मंत्री जी का यहां कहना बड़ी dichotomy है, आपस में बड़ी तरदीद है। आपने कहा कि बिल्कुल fair and objective process चल रहा है। अगर यह fair and objective process है तो ये दोनों आदमी, एक आर्मी में 30 साल और दूसरा Air Force में 30 साल service करने के बाद भी लिस्ट से बाहर कैसे हैं? मेरे ख्याल में माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहिए कि process में गड़बड़ हो सकती है, अगर आप पहले ही कहेंगे कि process ठीक है तो फिर आपने इसमें क्या करना है? ...(**व्यवधान**)... यह मुझे आपसे अनिवार्य रूप से कहना है। ...(**व्यवधान**)...

---

†**جناب غلام نبی آزاد:** یہ ٹیلی ویژن پر ڈسکشن چل رہا تھا اس طرح سے مانیئے گرہ منتری جی کا یہاں کہنا بڑی dichotomy ہے، آپس میں بڑی تردید ہے۔ آپ نے کہا کہ بلکل fair and objective process چل رہا ہے۔ اگر یہ fair and objective process ہے تو یہ دونوں آدمی، ایک آرمی میں تیس سال اور دوسرا ائیرفورس میں تیس سال سروس کرنے کے بعد بھی لسٹ سے باہر کیسے ہیں؟ میرے خیال میں مانیئے گرہ منتری جی کو کہنا چاہیئے کہ پرسیز میں گڑبڑ ہوسکتی ہے، اگر آپ پہلے ہی کہیں گے پروسیز ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ ...(مداخلت)... یہ مجھے آپ سے ضروری طور پر کہنا ہے ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu script.

12.00 Noon

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: एक question इन्होंने यहां उठाया। ...(**व्यवधान**)... सरकार और पार्टी को एक भाषा में बोलना चाहिए - कोई कहता है कि हमने किया, कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد:** ایک کوئیشچن انہوں نے یہاں اٹھایا ۔۔(مداخلت)۔۔۔ سرکار اور پارٹی کو ایک بھاشا بولنا چاہیئے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کیا، کوئی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا۔۔(مداخلت)۔۔

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, as there is no time,

आप नाम नोट करके सभी माननीय सदस्यों को लिखित रूप में उत्तर भेज दीजिए। ...(**व्यवधान**)... धन्यवाद।

श्री राजनाथ सिंह: धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... The Home Minister has taken note of all the suggestions and also the clarifications. Please go through it. I really feel sorry that I could not allow the Home Minister earlier. Normally it does not happen, but today, at least, we had an opportunity to hear the Home Minister. Many doubts have been clarified but still there are some doubts in the minds of the hon. Members. So, please take care of them and then send them answer. Question Hour. ...*(Interruptions)*... Question No.181. Mr. Minister. ...*(Interruptions)*... कृपया आप बैठ जाइए।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, at 1 o'clock. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Today is Friday. ...*(Interruptions)*... Please. What can I do? ...*(Interruptions)*... I have been cautioning the hon. Members. ...*(Interruptions)*... All the hon. Members, who want to go, please go quietly. ...*(Interruptions)*... If you want to remain, please remain quietly. ...*(Interruptions)*.. Please.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Subsidy for sugar sector

*181.SHRI T. RATHINAVEL: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government has approved a subsidy of ₹5.5 per quintal of sugarcane crushed during the 2017-18 season to help sugar mills clear more than ₹ 19,000 crore dues to cane growing farmers;

†Transliteration in Urdu script.